टीसीएस बनी सबसे बड़ी कंपनी

नई दिल्ली : टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) गुरुवार को फिर से देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) के एमकैप को पार कर गया। आरआइएल के शेयरों में गुरुवार को लगातार चौथे सत्र में गिरावट रही। चार दिनों में इसके शेयर बीएसई पर 10.79 फीसद गिर चुके हैं। आरआइएल का एमकैप गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद बीएसई पर 7,95,628.55 करोड़ रुपये रहा।

अगर भारत को 9-10 फीसद तक की विकास दर पर पहुंचना है तो रेस्तरां उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

– अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

सेंसेक्स	37,558.91	▼ 230.22
निफ्टी	11,301.80	▼ 57.65
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 32,890	▲ ₹40
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 38,220	(बदलाव नहीं)
$ डॉलर	₹ 69.94	▲ ₹0.23
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 69.69	

जॉनसन एंड जॉनसन ने बेबी शैम्पू को बताया सुरक्षित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कंपनी ने पहले हुई जांच के तरीकों पर उठाया सवाल
- कोलकाता की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में अब हो रही है जांच
- कंपनी ने कहा – संबंधित रसायन की मिलावट की कोई वजह नहीं

दुनिया की दिग्गज फार्मास्युटिकल व एफएमसीजी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि उसके उत्पाद बच्चों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। खासतौर पर बेबी शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड नामक रसायन को लेकर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह अपने उत्पाद में न तो फॉर्मल्डिहाइड और न ही कोई ऐसा कोई रसायन मिलाती है जिससे फॉर्मल्डिहाइड निकलता हो। कंपनी ने राजस्थान ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की जांच रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद बेबी शैम्पू के नमूनों की जांच अब कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में हो रही है।

राजस्थान में जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू के दो बैच की जांच में फॉर्मल्डिहाइड पाए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद राजस्थान और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने शैम्पू की बिक्री पर रोक लगा दी। दैनिक जागरण से बातचीत में जॉनसन एंड जॉनसन के प्रवक्ता ने बेबी शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड होने की संभावना को नकारा है। कंपनी का कहना है कि ऐसा होना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वह शैम्पू के निर्माण में न तो फॉर्मल्डिहाइड और न ही ऐसे किसी रसायन का इस्तेमाल करती है जिससे इसका रिसाव होता हो। कंपनी ने सवाल किया कि वह ऐसा करके अपने 125 वर्ष के ग्लोबल बेबीकेयर ब्रांड के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है।

यह पूछने पर कि क्या कंपनी अपने उत्पादों में फॉर्मल्डिहाइड की जांच करती है, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि वह इसका परीक्षण करती है। कंपनी ने कहा कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, उत्पाद निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान के प्रबंधन, क्वालिटी सिस्टम और टेस्टिंग के प्रत्येक स्तर पर जांच से यह सिद्ध हुआ है कि वह बेबी शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलाती। कंपनी ने इसकी जानकारी सरकार को भी दी है। कंपनी का कहना है कि वह डीएंडसी अधिनियम और उसके नियमों के तहत निर्धारित सभी मानकों का पालन करती है। उसका दावा है कि उसके उत्पाद इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं।

इस मामले में अब सवाल राजस्थान में हुई जांच के तरीकों पर भी उठने लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि राजस्थान की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने नमूनों की मात्रा और जांच के तरीके को भी कंपनी से साझा करने से इन्कार कर दिया है। लेबोरेटरी ने जांच के बाद केवल अपना निर्णय ही सार्वजनिक किया है। इसी वजह से कंपनी ने जांच के इन नतीजों को चुनौती दी है जिसके चलते अब कोलकाता की सेंट्रल लेबोरेटरी में जांच कराई जा रही है।

वोडा-आइडिया के अपने शेयर वोडाफोन ने रखे गिरवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वोडाफोन पीएलसी ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अपने सारे शेयर सात विदेशी बैंकों के हाथों गिरवी रखे हैं। वर्तमान में आइडिया के साथ संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी में वोडाफोन पीएलसी की 44.39 फीसद हिस्सेदारी है। शेयर बाजारों को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपनी पूरी 44.39 फीसद हिस्सेदारी सात विदेशी बैंकों को गिरवी रखी है। गुरुवार को शेयर बाजारों में कंपनी के शेयरों के भाव के हिसाब से इतने शेयरों की कीमत 18,000 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा बनती है।

वोडाफोन ने कहा कि वोडाफोन ग्रुप कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के तहत एचएसबीसी कॉरपोरेट ट्रस्टी कंपनी (यूके) लिमिटेड के पक्ष में ये शेयर गिरवी रखे गए। एचएसबीसी कॉरपोरेट ट्रस्टी (यूके) लिमिटेड छह कंपनियों के लिए ट्रस्टी की भूमिका निभा रही है। ये सभी कंपनियां भारत के बाहर स्थापित की गई हैं।

रिलायंस ग्रुप पर दिवालिया प्रक्रिया की पहली गाज

- एनसीएलटी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए स्वीकारा

मुंबई, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही आरकॉम अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित होने वाली पहली कंपनी बन गई। एनसीएलटी ने आरकॉम को मुकदमेबाजी में बीते 357 दिनों की अवधि को प्रक्रिया से बाहर रखने की भी अनुमति दे दी।

एनसीएलटी ने आरकॉम के बोर्ड को भंग कर दिया और कंपनी के कामकाज को देखने के लिए एक नए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) की नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई वाले 31 बैंकों के समूह को कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) गठित करने की भी अनुमति दे दी गई। पिछली सुनवाई में आरकॉम ने अपने पुराने आरपी के जरिये यह मांग की थी कि इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से 357 दिनों की अवधि (30 मई 2018 से 30 अप्रैल 2019 तक) को बाहर किया जाए। पिछले आरपी ने इस अवधि को प्रक्रिया से बाहर निकालने की मांग इसलिए की थी कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरुआती इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

वीपी सिंह और आर दुरईसामी की पीठ ने कहा कि मामले पर नियमों के तहत आगे बढ़ा जाना चाहिए और दिशानिर्देशों को देखते हुए ट्रिब्यूनल आरकॉम के साथ रिलायंस इन्फ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम के लिए भी अवधि को प्रक्रिया से बाहर निकाले जाने की अनुमति देता है। आरकॉम ने दो साल पहले उसने अपना परिचालन बंद कर दिया था। बैंक्रप्सी से बचने के लिए कंपनी ने अपना स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो को बेचने की भी कोशिश की थी।

वजह ▶ आरओसी को मिले कंपनी कानून के उल्लंघन के संकेत

जेट एयरवेज के निवेशक की तलाश में फंसा पेच

एक ब्रिटिश निवेशक ने किया था नरेश गोयल के साथ का दावा, गोयल ने किया खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नया निवेशक तलाशने के लिए वित्तीय बोली की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही जेट एयरवेज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ ब्रिटिश स्टार्ट-अप एयरलाइन के मालिक जेसन उन्सवर्थ के कंसोर्टियम में भागीदार होने से नरेश गोयल ने इन्कार किया है। वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जेट के प्रमोटरों द्वारा 5,000 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इससे नया निवेशक मिलने की कंपनी के कर्जदाताओं की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने जेट एयरवेज के खातों की जांच में एयरलाइन द्वारा कंपनी कानून के उल्लंघन के कुछ मामले पाए हैं। कंपनी रजिस्ट्रार ने बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के अध्ययन के बाद मंत्रालय तय करेगा कि इन मामलों की आगे और जांच कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि उसे लगा कि जेट एयरवेज के प्रमोटरों ने एयरलाइन का पैसा दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किया है तो फिर इस पूरे मामले की जांच सीरियस फ्रॉड ऑफिस (एसएफआइओ) को सौंपी जा सकती है।

कंपनी रजिस्ट्रार ने जेट के खातों की जांच अरविंद गुप्ता नामक व्यक्ति की शिकायत पर की है। गुप्ता वही हैं जिन्होंने आइसीआइसीआइ-वीडियाकॉन मामले की शिकायत की भी थी। जेट के विरुद्ध शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रमोटरों ने एयरलाइन की 5125 करोड़ रुपये की रकम को खाड़ी देशों में स्थित कुछ कंपनियों में डायवर्ट करने का प्रयास किया था। इससे पहले फरवरी में आयकर विभाग ने भी अपनी जांच में जेट एयरवेज पर 600 करोड़ रुपये की कर चोरी के सबूत पाए थे।

इस बीच ब्रिटेन की एक स्टार्ट-अप एयरलाइन के मालिक जेसन उन्सवर्थ के दावे पर नरेश गोयल के आपत्ति जताने से जेट के लिए नए निवेशक की तलाश की कोशिशों को एक और झटका लगा है। उन्सवर्थ ने पिछले दिनों एसबीआइ की अगुआई वाले बैंकों के समूह के समक्ष देर से पेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोली में दावा किया था कि उसके कंसोर्टियम में जेट के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल भी शामिल हैं। अपने ट्वीट में उन्सवर्थ ने लिखा कि मेरे कंसोर्टिसम में माई वर्ल्ड वेंचर के अक्षय उत्तम, फ्यूचर ट्रेंड कैपिटल के ललित वर्मा, रेडक्लिफ कैपिटल के धीरज और मल्हार हॉस्पिटैलिटी के सचिन नलवाडे के अलावा जेट एयरवेज के प्रमोटर नरेश गोयल भी शामिल हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ाने शुरू करने के लिए 2005 में एटमॉस्फियर इंटरकांटिनेंटल एयरलाइंस की स्थापना करने वाले उन्सवर्थ लगातार जेट एयरवेज में निवेश की इच्छा जता रहे हैं।

एमसीए का आंकड़ा भरोसेमंद : श्रीनिवास

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठे नए संदेह के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़े पूरी तरह से भरोसेमंद हैं और यह कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। यह देखना सांख्यिकी अधिकारियों का काम है कि जीडीपी की गणना के लिए कौन से आंकड़े उपयोगी हैं और कौन से नहीं। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि मंत्रालय का एमसीए-21 पोर्टल एक भरोसे पर आधारित सिस्टम है, क्योंकि वहां वही सूचनाएं दर्ज होती हैं, जो कंपनियां जारी करती हैं।

सेवा क्षेत्र पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी की गणना में उपयोग किए गए एमसीए-21 सिस्टम में करीब 36 फीसद कंपनियों का या तो पता नहीं लगाया जा सका या फिर उसके बारे में ठीक से सूचनाएं नहीं दर्ज हैं। एमसीए-21 में कॉरपोरेट फाइलिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित रखा जाता है।

श्रीनिवास ने कहा कि यहां दर्ज सूचनाएं कंपनियों के डिस्क्लोजर्स हैं और कंपनियों को ही उनका सत्यापन करना है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि आयोग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी आंकड़ों का विश्लेषण कर एक सर्वोत्तम निष्कर्ष पर पहुंचने की कवायद शुरू करने जा रहा है। इस कवायद को आयोग के वरिष्ठ सदस्य अंजाम देंगे।

आइएलएफएस मामले में रेटिंग एजेंसियों पर कार्रवाई संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्तीय संकट में फंसी एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) की जांच के दायरे में देश की कुछ नामी-गिरामी रेटिंग एजेंसियां फंसती नजर आ रही हैं। कंपनी कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी गंभीर अपराध जांच शाखा (एसएफआइओ) को इस कंपनी के निवेश प्रपत्रों की रेटिंग करने वाली केयर रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग, इकरा लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं।

इन रेटिंग एजेंसियों पर आरोप है कि इन्होंने नियमों को ताक पर रख कर आइएलएंडएफएस के ऋण प्रपत्रों को ज्यादा की रेटिंग दी। सूत्रों के मुताबिक इन चारों रेटिंग एजेंसियों से पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसको लेकर पूंजी बाजार नियामक सेबी और बैंकिंग नियामक आरबीआइ से भी संपर्क किया गया है, ताकि गड़बड़ियों के तह तक जाया जा सके।

सूत्रों का कहना है कि इन रेटिंग एजेंसियों के स्तर पर यह गड़बड़ी तब की गई है जब रेटिंग कंपनियों को लेकर पहले की नीतियो को सख्त बनाया जा चुका है। नियामक एजेंसियों की आरबीआइ गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली हर तिमाही बैठक में रेटिंग एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा होती है। आइएलएंडएफएस में पिछले वर्ष सितंबर में भारी वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि पिछले दो वर्ष से यह वित्तीय संकट से जूझ रही थी लेकिन रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट की वजह से मामला छिपा था। कंपनी पर इस वक्त 91 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है।

वास्तविक भारत की तस्वीर दिखाएगा सैमसंग का अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने देशभर में अपना डिजिटल कैंपेन 'इंडिया रेडी एक्शन' लांच किया है। इसके कैंपेन के तहत युवाओं और मिलेनियल कहलाने वाले साल 2000 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को वास्तविक भारत के वीडियो बनाकर उन्हें साझा करने का मौका देगा। कंपनी के इस कैंपेन का मकसद भारत से जुड़ी कुछ अवधारणाओं को बदलना है।

महीनाभर चलने वाले इस कैंपेन के जरिए युवाओं को 60 सेकेंड का वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर शेयर करने को कहा जाएगा। यह वीडियो किसी स्थान, भोजन, मनोरंजन और संस्कृति विषयों पर बनाया जा सकता है। सैमसंग इंडिया के चीफ मार्केटिंग आफिसर रंजीवजीत सिंह ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी सामाजिक रूप से जागरूक है, जो भारत को लेकर जोश में रहती है। यह पीढ़ी डिजिटल दुनिया की निवासी है जो 'एरा ऑफ लाइव' में जी रहे हैं। कंपनी हर हफ्ते सात विजेताओं को गैलेक्सी ए70 फोन पुरस्कार में देगी। सभी वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सैमसंग इंडिया को टैग कर हैशटैग इंडियारेडीएक्शन, हैशटैगसिटी और हैशटैगथीम के साथ पोस्ट कर सकते हैं। सभी पोस्ट को भारत के इंटरैक्टिव मैप पर प्रदर्शित किया जाएगा।

वार्ता से पीछे हट रहा चीन चुकानी होगी कीमत : ट्रंप

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि दोनों देशों की वार्ता में बनी सहमति से चीन पीछे हटा है। उसने साथ ही कहा कि जब तक चीन उसके कर्मचारियों को धोखा देना बंद नहीं करता, तब तक अमेरिका चीन पर नया शुल्क लगाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने कहा कि चीन के 200 अरब डॉलर के आयात पर शुक्रवार से ही शुल्क 10 फीसद से बढ़कर 25 फीसद हो जाएगा।

चीन के उप प्रधानमंत्री लियु हे और अमेरिका के शीर्ष व्यापार अधिकारी की दो दिवसीय वार्ता वाशिंगटन में गुरुवार और शुक्रवार को हो रही है। फ्लोरीडा में बुधवार को एक रैली में ट्रंप ने कहा कि चीन वार्ता से पीछे हट रहा है और यदि सहमति नहीं बन पाई, तो इसकी कीमत चीन को चुकानी होगी। चीन हमारे कर्मचारियों को धोखा नहीं दे सकता है। यदि हमारे बीच समझौता नहीं हुआ, तो हर साल 100 अबर डॉलर से अधिक वसूलने में कुछ बुराई नहीं है।

अमेरिका की चेतावनी का जवाब देते हुए चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ट्रेड वार में अपने हितों की रक्षा के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है। उसने हालांकि उम्मीद जताई कि अमेरिका एक पक्षीय कदमों से नहीं बल्कि वार्ता से मुद्दों को सुलझाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि चीन के रुख में बदलाव नहीं आया है। चीन किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। उसने सभी संभावित निष्कर्षों का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। इसके बारे में हालांकि उन्होंने कुछ विस्तार से नहीं बताया।

इस बीच, अमेरिकी बाजार में चाइना मोबाइल के प्रवेश पर रोक लगाने के एक प्रस्ताव पर गुरुवार को अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन (एफसीसी) में मतदान होगा। चाइना मोबाइल चीन की सरकारी दूरसंचार कंपनी है। एफसीसी के चेयरमैन अजीत पई ने सीनेट एप्रोप्रिएशंस सबकमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जनरल गवर्मेंट के सदस्यों से एक सुनवाई के दौरान कहा कि चाइना मोबाइल को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने से रोकने के मेरे प्रस्ताव पर पक्ष में मतदान होने की उम्मीद है।

ट्रेड वार से भारत को भी होगा नुकसान

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- हालांकि भारतीय निर्यात में 11 अरब डॉलर का इजाफा संभव : अंकटाड

भारत पर असर

1. अमेरिका में ब्याज दरों के और बढ़ने के आसार : भारत से निकल सकते हैं संस्थागत निवेशक
2. यूरोपीय संघ भी उठा सकता है संरक्षणवादी कदम, भारतीय निर्यात पर पड़ेगा असर
3. अंतरराष्ट्रीय बांड्स बाजार पर भी होगा उल्टा असर, प्रभावित होगी भारतीय बैंकों की कमाई
4. वैश्विक अस्थिरता से क्रूड के महंगा होने का डर, महंगा होगा पेट्रोल व डीजल
5. चीन बंद करेगा अमेरिकी सोयाबीन का आयात, भारतीय सोयाबीन के लिए संभावना

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के और गहराने के पूरे आसार बनते जा जा रहे हैं। ट्रेड वार से आने वाले दिनों में निर्यात में कुछ फायदा होता तो दिख रहा है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर को देखते हुए भारत को नुकसान ज्यादा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होने और डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं की कीमत में अस्थिरता होने का खामियाजा भारतीय अर्थव्यवस्था का उठाना पड़ सकता है। हालांकि भारत के लिए चीन में 11 अरब डॉलर का नया बाजार भी बन सकता है।

भारत और चीन के बीच कृषि उत्पादों की राह में अड़चनें दूर करने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक भी हुई। बैठक में चीन को तीखे मिर्च वाले खाद्य उत्पादों के निर्यात को लेकर एक सहमति पर भी संधि हुई है। लेकिन भारत जिन महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति चाहता है, उसको लेकर चीन का रवैया अभी सकारात्मक नहीं है। भारत ने इससे पहले चीन को 380 ऐसे उत्पादों की सूची सौंपी है जिसे वह निर्यात करना चाहता है ताकि दोनो देशों के बीच 51 अरब डॉलर के कारोबारी घाटे को पाटा जा सके। इसमें टैक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स के अलावा सोयाबीन, अरंडी, अलसी जैसे कई कृषि उत्पाद हैं जिसके लिए चीन अभी अमेरिका पर निर्भर है। भारत में नई सरकार के आने के बाद इस बारे में फिर गंभीरता से बात होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका-चीन ट्रेड वार से भारत को 11 अरब डॉलर का बाजार मिल सकता है। इसके लिए चीन और भारत सरकार के बीच राजनीतिक स्तर पर सहमति बनानी होगी।

निर्यात के फायदे को अगर नजरंदाज कर दें तो अर्थव्यवस्था के दूसरे मोर्चे पर भारतीय बाजार को भी भारी अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर के बाजार शुक्रवार का इंतजार कर रहे हैं जब अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत का पटाक्षेप होगा। पिछले तीन महीने से डॉलर के मुकाबले मजबूत चल रहा भारतीय रुपया पिछले तीन कारोबारी दिनों में 54 पैसे का गोता लगा चुका है। इसके लिए इस अस्थिरता को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भारत की दूसरी चिंता यह है कि अगर चीन से आयातित उत्पादों पर अमेरिका शुल्क बढ़ाता है तो यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी अपने कारोबार की संरक्षा के लिए इसी तरह का कदम उठा सकती हैं।

रिलायंस ब्रांड्स ने किया हैम्लेज टॉय स्टोर का अधिग्रहण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने हैम्लेज ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण के साथ खिलौनों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की घोषणा की है। रिलायंस ब्रांड्स ने हांगकांग स्थित सी बैनर इंटरनेशनल होल्डिंग्स से इसके 100 फीसदी शेयर खरीदने का करार किया है। सी बैनर इंटरनेशनल होल्डिंग्स हैम्लेज ब्रांड की ओनर है। सन 1760 में स्थापित हैम्लेज दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खिलौना शॉप है। हैम्लेज अपने खिलौनों की बेहतरीन गुणवत्ता और विस्तृत रेंज के बेहतरीन मॉडल के साथ विस्तार करने में सफल रही है और बच्चों की पसंदीदा बनी हुई है। कंपनी ने थिएटर और मनोरंजन के साथ अपने रिटेल नेटवर्क का विस्तार किया है।

दुनियाभर में 167 स्टोर : 18 देशों में हैम्लेज के 167 स्टोर हैं। भारत में रिलायंस ही हैम्लेज की मास्टर फ्रैंचाइजी है और देश के 29 शहरों में 88 स्टोर्स का संचालन कर रही है। हैम्लेज ने अपना प्रमुख स्टोर रीजेंट स्ट्रीट लंदन में 1881 में खोला था। यह प्रमुख स्टोर सात मंजिलों में फैला है और 54,000 वर्ग फीट से अधिक के एरिया में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह लंदन का एक प्रमुख टूरिस्ट स्थल भी है और पूरी दुनिया से लोग इस टॉय स्टोर को देखने और इसमें खरीदारी के लिए आते हैं। इस अधिग्रहण के साथ रिलायंस ब्रांड्स को एक प्रमुख बढ़त मिलेगी और ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में एक प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरेगी। हर साल इस स्टोर में 50 लाख से अधिक लोग आते हैं।

इस बारे में रिलायंस ब्रांड्स के प्रेसिडेंट व सीईओ दर्शन मेहता ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमने भारत में हैम्लेज ब्रांड के तहत खिलौनों की रिटेल बिक्री में बड़ी सफलता हासिल की है और इसे एक लाभप्रद बिजनेस में बदला है। 250 से अधिक साल पुराने इंग्लिश टॉय रिटेलर ने दुनियाभर में रिटेलिंग में बड़े स्तर पर नए प्रयोगों की शुरुआत और सफलता हासिल की। हैम्लेज ब्रांड और बिजनेस के वैश्विक अधिग्रहण के साथ रिलायंस अब ग्लोबल टॉय रिटेलिंग में एक प्रमुख कंपनी बन कर उभरेगी।

पेरिस से मुंबई आ रहे फ्रांसीसी विमान को ईरान में करनी पड़ी आपात लैंडिंग

- क्रू मेंबर और सभी यात्री सुरक्षित, चेकिंग के बाद दुबई गया विमान
- एयरलाइन ने कहा, वेंटिलेशन सर्किट में खामी के चलते उतारा गया विमान

तेहरान, एपी : पेरिस से मुंबई जा रहे फ्रांसीसी एयरलाइंस के एक विमान को तकनीकी गड़बड़ी के चलते बुधवार को ईरान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कई घंटे के बाद उसे दुबई भेजा गया। एयरलाइन ने इसकी जानकारी दी।

सस्ती विमान सेवा मुहैया कराने वाली एयर फ्रांस की सहायक एयरलाइंस जून ने कहा कि उसके एयरबस ए 340 को मध्य ईरानी शहर इसफहान में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट संख्या एएफ 218 की वेंटिलेशन सर्किट में गड़बड़ी आ गई थी, जिसके बाद उसे एहतियातन उतारना पड़ा।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से यात्रियों को आवश्यक सेवाएं मुहैया कराई गईं। एजेंसी के मुताबिक विमान में सवार सभी लोग सही सलामत थे।

वहीं, एयर फ्रांस ने कहा कि एयरपोर्ट पर स्थानीय मेंटिनेंस टीम ने विमान की जांच पड़ताल की। इसके बाद उसे दुबई के अल मक्तून इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया। एयर फ्रांस ने यह भी बताया कि दूसरी एयरलाइंस के जरिए यात्रियों को जल्द से जल्द मुंबई भेज दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में नॉर्वेजियन एयर के बोइंग 737 मैक्स विमान को भी ईरान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। वह विमान दुबई से ओस्लो की उड़ान पर था।

यात्रियों को तो अगले ही दिन दूसरी एयरलाइंस से ओस्लो भेज दिया गया था। लेकिन अमेरिका निर्मित नॉर्वेजियन एयर का विमान मरम्मत के इंतजार में कई हफ्ते तक ईरान में ही खड़ा रहा। क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों के चलते ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से विमान के कलपुर्जों को ईरान भेजने की कागजी कार्यवाही में ज्यादा वक्त लगा था।

लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान की वियना में इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मुंबई से मंगलवार की सुबह लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान को तकनीकी खराबी के चलते ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में तीन सौ यात्री थी, जिनमें से ज्यादातर भारतीय थे।

वियना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये यात्री 24 घंटे तक फंसे रहे। एयर इंडिया की तरफ से कोई सही जानकारी नहीं मिल पाने पर यात्रियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी ट्वीट कर मदद मांगी थी। यात्रियों ने एयरलाइंस के कर्मचारियों के व्यवहार को भी बेहद निराशाजनक बताया था।

यूनिटेक के रिटेलरों से तिहाड़ की सुविधाएं वापस होंगी

- सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटरों से सहयोग न करने पर दिया आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूनिटेक लिमिटेड के रिटेलरों के फॉरेंसिक ऑडिट में सहयोग न करने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद उसके प्रमोटरों संजय चंद्रा और उसके भाई अजय चंद्रा को दी जाने वाली सभी सुविधाएं वापस लेने को कहा है।

सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा कि तिहाड़ जेल में वर्ष 2017 से कैद चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ जेल के मैनुअल के अनुसार एक साधारण कैदी की तरह ही रखा जाए। वर्ष 2017 में सर्वोच्च अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिया था कि वह चंद्रा बंधुओं को अपनी कंपनी के अधिकारियों और वकीलों के साथ बैठक करने की सुविधा दी जाए ताकि वह धन की व्यवस्था कर सकें। ताकि उनके होम बायर्स का पैसा लौटाया जा सके और अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा भी किया जा सके।

तब यह भी कहा गया था कि जेल में उनसे मिलने वालों को सामान्य विजिटिंग ऑवर में ही आने दिया जाए। लेकिन गुरुवार को जब फॉरेंसिक ऑडिटर ने अदालत को बताया कि यूनिटेक उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उनके पास यूनिटेक के मामलों की सीबीआइ जांच का आदेश देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर.शाह की पीठ ने सीबीआइ जांच के बारे में तत्काल कोई सीधा आदेश नहीं दिया लेकिन पीठ ने कहा कि उसे अगली सुनवाई में महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल के सहयोग की जरूरत होगी।

पीठ ने कहा कि वह महाधिवक्ता से यह भी जानना चाहेगी कि क्या सरकार घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए यूनिटेक समूह और उसकी अनुषंगियों का प्रबंधन अपने हाथों में ले सकती है। पीठ ने यूनिटेक की अटकी परियोजनाओं को केंद्रीय निर्माण एजेंसियों के जरिये सरकार की ओर से पूरा कराने के बारे में भी महाधिवक्ता की राय जानने की इच्छा जाहिर की। मामले में न्यायालय का सहयोग कर रहे अधिवक्ता पवन श्री अग्रवाल ने बताया कि गुड़गांव नगर निगम ने यूनिटेक की सैकड़ों करोड़ की एक संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। पीठ ने इस बारे में कहा कि मामले की सुनवाई संपन्न होने तक नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है।

'अवैध विदेशियों की सशर्त रिहाई पर विचार संभव'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह असम के बंदी केंद्रों से अवैध विदेशियों की सशर्त रिहाई पर विचार कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अवैध विदेशियों की रिहाई के लिए ऐसी कुछ शर्तें लगा सकता है, जिसके तहत उन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी कानूनी कार्यवाहियों के लिए अदालत या संबंधित प्राधिकरण के सामने पेश होना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से अवैध प्रवासियों से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए लगभग एक हजार विदेशी ट्रिब्यूनल गठित करने के तौर तरीकों पर काम करने को कहा है। कोर्ट ने न्याय मित्र वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह बंदियों की रिहाई के लिए लगाई जा सकने वाली अनुकूल शर्त